Yes, Sir. In August, 1990, Asian Development Bank had proposed assistance to an India Equity Fund (IEF), to be launched jointly with Unit Trust of India. The principal investment objective of the Fund is long term capital appreciation through investment in equity and convertible debenture issues of Indian Companies, particularly the issues of new companies.

**कच्छ क्षेत्र में तस्करी**

2946. **डा० बापू कालदाते:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कच्छ की खाड़ी अवैध व्यापार का केन्द्र बन गई है;

(ख) इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ग) वर्ष 1991 के दौरान सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त की गयी तस्करी की वस्तुओं का मूल्य क्या है तथा उनकी मात्रा क्या है तथा इसमें शामिल उन लोगों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध अभियोग चलाये गये; और

(घ) सरकार समुद्र तट रेखा क्षेत्र की निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर):** (क) से (घ): उपलब्ध रिपोर्टों तथा किये गये अभिग्रहणों से पता चलता है कि कच्छ की खाड़ी सोने और चांदी सहित निषिद्ध माल की तस्करी के लिए सुगम्य बनी हुई है। वर्ष 1991 के दौरान, कच्छ की खाड़ी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लगभग 39.72 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया था और 51 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये थे।

सीमाशुल्क प्राधिकारी कच्छ की खाड़ी सहित तस्करी सबंधी गतिविधियों के प्रति सर्तक रहते हैं। आसूचना तंत्र को तस्करी के प्रति चुस्त कर दिया गया है और समुद्री तथा सड़क मार्गों की लगातार गश्त की जाती है। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ट तालमेल बनाए रखा जाता है।

**Bank Employees Federation of India opinion against Narasimham Committee report**

2947. SHRI BEKAL UTSAHI:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the General Secretary, Bank Employees Federation of India, regarding the various recommendations of the Narasimham Committee, especially those regarding expansion of capital base of nationalised banks and rural branches thereof and deployment of bank resources and priority sector advances; and

(b) if so, what is the Government's reaction thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) No representation has been received from the General Secretary, Bank Employees Federation of India in regard to the recommendations of the Committee on the Financial System (Narasimham Committee).

(b) Does not arise.

**Concept of non-voting shares**

2948. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have examined the concept of non-voting shares; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) The Study Group under the Chairmanship of Shri M.J. Pherwani for reviewing the existing guidelines relating to capital issues and for evolving guidelines for issue of new financial instruments has recommended the introduction of non-voting shares. Section 85 of the Companies Act, 1956 provides for only two kinds of share capital. Accordingly, the Department of